प्राकृतिक चिकित्सा से संबंधित अनुसंधान परियोजना के क्रियान्वयन में विलम्ब

2478. **श्री शंकर सिंह बघेला :**

श्री प्यारेलाल खंडेलवाल :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 23 जून, 1985 के "जनसत्ता" में प्रकाशित उस समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें यह बताया गया है कि स्वास्थ्य मंत्रालय पर स्वामी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी के सतत प्रभाव के कारण प्राकृतिक चिकित्सा से संबंधित करोड़ों रुपये की अनुसंधान परियोजना और विस्तार योजनाएं खटाई में पड़ी हुई हैं;

(ख) उन परियोजनाओं और विस्तार योजनाओं के नाम क्या हैं जिन पर काम ठप्प पड़ा हुआ है और यह काम कब से ठप्प पड़ा हुआ है ; और

(ग) इसमे सरकार को अब तक कितनी हानि हुई है ?

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाणा) : (क) से (ग) इस मंत्रालय ने 23 जून, 1985 के "जनसत्ता" में प्रकाशित समाचार को देखा है । प्राकृतिक चिकित्सा की नई परियोजनाओं तथा विस्तार योजनाओं को अनुदान वैज्ञानिक वित्तीय सलाहकार समिति तथा परिषद के शासी निकाय की सिफारिश पर केन्द्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा मंजूर किया जाता है । छठी पंचवर्षीय योजना (1980–85) में इस परिषद के लिये रखे गये 144 लाख रुपयों में से वास्तव में 89.67 लाख रुपये खर्च हुये थे । नई परियोजनाओं और विस्तार योजनाओं के लिये धन मंजूर न करने के कारण सरकार को कोई नुकसान होने की सूचना नहीं दी गई है ।

Abolition of brand names of drugs

2479. SHRI DHULESHWAR MEENA: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that foreign drug companies in India spend a stupendous amount i.e., 25 per cent of their sales turnover on promotional expenditure and brand names of drugs;

(b) whether Government are aware of thousands of brand names circulating in India for some basic drugs; if so, their approximate number as per Government's information;

(c) whether these multi-national pharmaceutical corporations are using not only high pressure sales techniques but also promote product differential under which the same basic drug is marketed under different brand names; and

(d) if so, what action Government propose to take to abolish the brand names to reduce the prices of pharmaceuticals without affecting quality?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF HEALTH (SHRI YOGENDRA MAKWANA): (a) to (c) This Ministry has no information.

(d) The Delhi High Court in the judgement delivered on 13th August, 1982 declared that laying down *inter-alia* single ingredient preparation of certain drugs shall be marketed only under generic names, as illegal and *ultra vires* of the Constitution. The Government have preferred an appeal (Special Leave Petition) in the Supreme Court. The Special Leave Petition has been admitted. The matter is, therefore, sub-judice.

Creation of new trades in the Corps of Electrical and Mechanical Engineering

2480. SHRI LAXMI NARAIN: Will the Minister of DEFENCE be pleased to state:

(a) whether the Expert Classification Committee (ECC) had identified certain trades being performed by other tradesmen in the Corps of Electrical and Mechnical Engineering and had recommended creation of seven new trades and to redesignate the existing tradesmen performing these duties, commensurating pay scales;

(b) whether it is a fact that in spite of Government orders issued in May, 1981